

बदलते परदृश्य के बीच भारत की विकास रणनीति

यह एडिटरियल 10/12/2023 को 'हद्वि बज़िनेसलाइन' में प्रकाशित ["Calibrating a strategy for India's future growth"](#) लेख पर आधारित है। इसमें वैश्विक और घरेलू परिवेश के संदर्भ में भारत के आर्थिक विकास के समकक्ष विद्यमान चुनौतियाँ एवं अवसरों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलम्ब के लिये:

[SWIFT](#), वर्ष 2007-2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, [Brexit](#), [वृद्धशील पूंजी उत्पादन अनुपात \(ICOR\)](#), [हरति ग्रडि पहल \(GGI\)](#), [वन सन](#), [वन वरल्ड](#), [वन ग्रडि \(OSOWOG\)](#), [राजकोषीय घाटा](#)।

मेन्स के लिये:

वैश्विक आर्थिक स्थितियों में बदलाव, निर्यात आधारित विकास रणनीति में गरिबट के पीछे कारण, निर्यात आधारित विकास रणनीति में गरिबट का भारत पर प्रभाव, इन परिवर्तनों का मुकाबला करने के लिये आवश्यक उपाय।

- वर्ष 2023-24 में भारत की वृद्धि दर वर्तमान में [भारतीय रज़िर्व बैंक](#) द्वारा 7% अनुमानित है जबकि [अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष \(IMF\)](#) और [वशिव बैंक](#) ने इसे 6.3% आँका है। अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश करने वाले इन तमाम अनुमानों के बीच भारत के निर्यात में गरिबट का रुख चिंता का कारण बन सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) की रिपोर्ट के अनुसार, शरम-प्रधान क्षेत्रों के वैश्विक निर्यात में भारत की हसिसेदारी पछिले 5 वर्षों से घट रही है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत की भविष्य की विकास रणनीति को संतुलित करने की आवश्यकता है।

बदलती वैश्विक परिस्थितियाँ कौन-सी हैं?

- वैश्वीकरण की प्रवृत्ति:** [रूस-यूक्रेन युद्ध](#) और [इज़राइल-हमास संघर्ष](#) जैसे जारी भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण [वि-वैश्वीकरण \(Deglobalization\)](#) की एक स्पष्ट वैश्विक प्रवृत्ति नज़र आती है।
- प्रतर्बिधों का आरोपण:** भू-राजनीतिक संघर्षों के परिणामस्वरूप कुछ देशों पर प्रतर्बिध लगाए गए हैं। इन प्रतर्बिधों के परिणामस्वरूप आपूर्ति शृंखलाएँ घटित हुई हैं और अंतरराष्ट्रीय नपिटान (international settlements) में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। [स्वफिट \(SWIFT\)](#) जैसी महत्त्वपूर्ण प्रणालियों तक सीमिति पहुँच, जो चुनदि देशों के लिये ही उपलब्ध है, ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है।
- वशिव की वास्तविक जीडीपी में गरिबट:** वशिव की वास्तविक जीडीपी वृद्धि में गरिबट के परिणामस्वरूप वैश्विक निर्यात मांग में कमी आई है। यह प्रवृत्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था में समग्र मंदी का प्रतर्बिध है, जो राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार तनाव और उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव जैसे कई कारकों द्वारा प्रकट होता है।
- अनश्चितता और मूल्य अस्थिरता:** आपूर्ति संबंधी अनश्चितताओं और मूल्य अस्थिरता के कारण भारत सहित कई देश आयातित पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, जिससे वैश्विक मांग में और कमी आई है।
- निर्यात आधारित विकास रणनीति में गरिबट:** [निर्यात आधारित विकास रणनीति \(Export led Growth strategy\)](#) एक आर्थिक विकास दृष्टिकोण है जो वदिशी बाज़ारों में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर निर्भर करती है। इस रणनीति को हाल के वर्षों में, विशेष रूप से [वर्ष 2007-2008 के वैश्विक वित्तीय संकट](#) और [2020-2021 की कोविड-19 महामारी के बाद कई चुनौतियों एवं सीमाओं का सामना करना पड़ा है।](#)
 - उदाहरण के लिये, भारत के मामले में [वर्ष 2003-04 से 2008-09 के दौरान निर्यात में सकल घरेलू उत्पाद की हसिसेदारी में तीव्र वृद्धि देखी गई।](#) वर्ष 2013-14 में यह 25% के शीर्ष स्तर तक पहुँच गया। वर्ष 2022-23 में यह 22.8% थी, जो वर्ष 2019-20 और 2020-21 में गरिकर 18.7% के नमिन स्तर पर आ गई।

निर्यात आधारित विकास रणनीति में गरिबट के पीछे कारण:

- वैश्विक मांग में मंदी:** संकट और महामारी ने कई विकसित एवं विकासशील देशों से निर्यात की प्रभावी मांग को कम कर दिया है, विशेष रूप से पर्यटन, वनिरिमाण और कमोडिटी जैसे क्षेत्रों में।
 - इससे कई निर्यात-उन्मुख अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात राजस्व एवं विकास संभावनाओं पर प्रतर्कूल प्रभाव पड़ा है।
- संरक्षणवाद का उदय:** संकट और महामारी ने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के बीच संरक्षणवादी उपायों और व्यापार तनाव की एक लहर भी पैदा कर दी

है, जैसे कि [अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध](#), [ब्रेगजिट \(Brexit\)](#) और आपूर्ति शृंखलाओं का कषेत्रीयकरण।

◦ इनसे नरियातकों के लिये अनश्चितताएँ एवं बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली कमज़ोर हुई है।

- **वेतन कटौती की सीमाएँ:** कई नरियात-आधारित विकास रणनीतियों ने प्रतस्पर्द्धात्मकता एवं लाभप्रदता बनाए रखने के लिये श्रमिकों के वेतन एवं आय को दमति करने पर भरोसा किया है। लेकिन इसके परिणामस्वरूप असमानता, सामाजिक असंतोष और घरेलू मांग की बाधाएँ बढ़ी हैं।
 - इसके अलावा, नमिन वेतन वाले देशों या स्वचालन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ प्रतस्पर्द्धा करना कठिन हो गया है।

नरियात आधारित विकास रणनीति में गरिबट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है?

- नरियात आधारित विकास रणनीति में **गरिबट का भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है**, क्योंकि यह देश के आर्थिक प्रदर्शन, रोज़गार सृजन और वैश्विक एकीकरण को प्रभावित करता है।
- कमज़ोर वैश्विक मांग, बढ़ता संरक्षणवाद और प्रतस्पर्द्धात्मकता में गरिबट जैसे विभिन्न कारकों ने **हाल के वर्षों में भारत के नरियात को मंद कर दिया है**।
 - इससे **भारत की जीडीपी वृद्धि में गरिबट आई है** क्योंकि देश की जीडीपी में नरियात की हस्सेदारी लगभग 19% है।
- इसने विशेष रूप से **परधान, रतन एवं आभूषण और फार्मास्यूटिकल्स जैसे श्रम-गहन कषेत्रों में रोज़गार सृजन को सीमति कर दिया है**।

भारत को क्या उपाय करने चाहिये?

- **घरेलू बचत को बढ़ावा देना:** बचत और नविश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करने के माध्यम से **घरेलू कषेत्र की बचत में गरिबट**, विशेष रूप से वित्तीय परसिंपत्तियों में गरिबट, को संबोधित किया जाना चाहिये। इसके अलावा, इस गरिबट में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण करना।
 - **उत्तर-कोवडि रुझानों की नगिरानी करना:** अस्थायी प्रतिक्रियाओं और संभावित नरितर परिवर्तनों के बीच अंतर करने के लिये घरेलू बचत में उत्तर-कोवडि रुझानों की लगातार नगिरानी एवं विश्लेषण करें। यदि गरिबट जारी रहती है तो रुझान को पलटने के उपाय लागू करना।
 - **घरेलू कषेत्र में नविश को प्रोत्साहित करना:** परिवारों को अपनी बचत को उत्पादक नविश में लगाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु **वित्तीय साक्षरता** एवं जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। सरकार और कॉर्पोरेट कषेत्र के लिये वित्तपोषण का एक स्थिर स्रोत सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय परसिंपत्तियों में नविश के लिये प्रोत्साहनों (incentives) का विकास किया जाए।
- **नविश दक्षता को अनुकूलित/इष्टतम करना:** नियमिती रूप से **वृद्धशील पूंजी - उत्पादन अनुपात (Incremental Capital-Output Ratio - ICOR)** का आकलन करें और नविश की दक्षता बढ़ाने के लिये इसे कम करने की दशा में कार्य करें। **यदि ICOR का स्तर नमिन है तो इससे उच्च प्राप्य वृद्धि (higher achievable growth) की स्थिति बन सकती है**, इसलिये संसाधन उपयोग की दक्षता में सुधार के प्रयास किये जाने चाहिये।
- **रोज़गार संबंधी चुनौतियों को संबोधित करना:** श्रम-बचत नवाचारों (labor-saving innovations) के बीच अद्वितीय जनसांख्यिकीय लाभ और रोज़गार सृजन की संभावित चुनौती की पहचान की जाए। गैर-कृषि और प्रौद्योगिकी-गहन कषेत्रों के लिये **कार्यबल तैयार करने हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल कार्यक्रमों के लिये संसाधन आवंटित करें**।
- **गैर-कृषि विकास को बढ़ावा देना:** कृषि से नरिमुक्त श्रम को अवशोषित करने के लिये गैर-कृषि विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान दें। ऐसी नीतियाँ लागू करें जो समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने के लिये **कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं और जेनरेटिव AI** सहित उत्पादकता बढ़ाने वाली अन्य प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण की सुविधा प्रदान करना।
- **जलवायु-अनुकूल विकास:** सेवा कषेत्र, जो अपेक्षाकृत जलवायु-अनुकूल कषेत्र है, पर बल देकर आर्थिक विकास को पर्यावरणीय संवहनीयता के साथ संरेखित करें। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये **ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव (Green Grids Initiative- GGI)** एवं **वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (One Sun One World One Grid- OSOWOG)** जैसी पहलों को जारी रखें और इन्हें संवर्द्धित करना।

राजकोषीय उत्तरदायित्व: सतत् आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिये राजकोषीय उत्तरदायित्व लक्ष्यों का पालन करना। उन नीतियों को प्राथमिकता देना जो संयुक्त **राजकोषीय घाटे** और ऋण-जीडीपी अनुपात को क्रमशः 6% और 60% तक कम कर सकें। इससे ब्याज भुगतान को प्रबंधित करने, सरकारी बचत को कम करने तथा अर्थव्यवस्था की समग्र बचत दर को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नषिकर्ष:

भारत एक बदलते वैश्विक परदृश्य का सामना कर रहा है जो वैश्वीकरण एवं आर्थिक अनश्चितताओं जैसे कारकों से चहिनति हो रहा है। नरियात-आधारित विकास मॉडल की चुनौतियों को हल करने की आवश्यकता स्पष्ट है। भारत को आगे बढ़ने के लिये घरेलू प्रतयास्थता, नवाचार और संवहनीय अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। व्यापार का ववधिकरण, शक्ति में नविश और राजकोषीय उत्तरदायित्व अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भारत अनुकूलनशीलता और रणनीतिक सुधारों को अपनाकर न केवल वर्तमान चुनौतियों से निपट सकता है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रतयास्थी एवं नवोन्मेषी शक्त के रूप में भी उभर सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारत की अर्थव्यवस्था और रोज़गार परदृश्य पर नरियात आधारित विकास रणनीति में गरिबट के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने और सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत के लिये आवश्यक रणनीतिक उपायों का सुझाव दीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. नरिपेक्ष तथा प्रतवियक्तावास्तवकि GNP में वृद्धिआर्थकि वकिस की ऊँची स्तर का संकेत नहीं करती, यदि: (2018)

- (a) औद्योगकि उत्पादन कृषिउत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में वफिल रह जाता है ।
- (b) कृषि उत्पादन औद्योगकि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में वफिल रह जाता है ।
- (c) नरिधनता और बेरोज़गारी में वृद्धि होती है ।
- (d) नरियात की अपेक्षा आयात तेज़ी से बढ़ता है ।

उत्तर: (c)

प्रश्न. कसिी दयि गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में आधिकारकि गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योकः (2019)

- (a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है ।
- (b) कीमत- स्तर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है ।
- (c) सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है ।
- (d) सार्वजनकि वतिरण की गुणवत्ता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है ।

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) को परभाषति कीजयि और उसके नरिधारकों की व्याख्या कीजयि । वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपनी संभाव्य जी.डी.पी. को साकार करने से रोकते हैं? (2020)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-s-growth-strategy-amidst-shifting-dynamics>